उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए चुनाव प्रचार मंगलवार 8 फरवरी को समाप्त हो गया। प्रथम चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा तथा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हस्तिनापुर में ट्रैक्टर पर बैठकर रोड शो किया और कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। इसी के साथ सचिन पायलट ने उत्तराखंड में मैंगलोर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार काजी निज़ामुद्दीन के पक्ष में भी प्रचार किया। इसके अलावा भी सचिन पायलट ने कई जनसभाओं को संबोधित करने के अलावा डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया।

जयपुर में दिनदहाड़े बंदूक की नोंक पर बैंक में 15 लाख रू. की लूट

चौमूं हाउस सर्किल स्थित सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दो नकाबपोश बदमाशों ने 20 मिनट में वारदात को अंजाम दिया

- बैंक के सी.सी.टी.वी. कैमरे और अलर्ट सिस्टम बंद था, गार्ड भी मौजूद नहीं था।
- पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, जांच के लिए आठ टीमें गठित।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 8 फरवरी । राजधानी जयपुर में चौमूं हाउस सर्किल स्थित सैन्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया में मंगलवार सुबह दो बदमाश दिनदहाड़े 15 लाख रु. लूट ले गये। बंदूक की नोंक पर नकाबपोश बदमाशों ने बैंक प्रबंधक मुकेश चौधरी व 10 ग्राहक व कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर दिया और 20 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए बाथरूम के गेट पर फायरिंग की और बैंककर्मी की स्कूटी से फरार हो गए। बदमाश एक ग्राहक से करीब पांच हजार रुपए भी लूटकर ले गए और कई लोगों के मोबाइल फोन भी छीने, जिन्हें भागते समय इधर-उधर फैंक गए। सूचना पर डीसीपी मृदुल कच्छावा सहित आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस की आठ टीमें इस पूरी वारदात के खुलासे में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह दो नकाबपोश बदमाश सुबह करीब 10 बजे परिवहन मार्ग पर मिशन कम्पाउंड की तरफ से पैदल आए। इनमें से एक बदमाश बैंक के अंदर घुस गया और दूसरा बाहर हथियार के साथ पहरा देता रहा। अंदर घुसे बदमाश ने गन पॉइंट पर सबसे पहले एक बैंककर्मी और दो ग्राहकों को लिया। इसके बाद बैंक प्रबंधक मुकेश चौधरी समेत करीब 10 ग्राहकों और कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद कैशियर महेंद्र सिंह की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर उससे लॉकर की चाबी मांगी। लॉकर में से बदमाश करीब 15 लाख रूपए बैग में भरकर बाहर आ गया और बाथरूम के गेट पर एक राउंड फायर कर दहशत फैला दी। इसके बाद बैंक के बाहर खड़ी किसी बैंककर्मी की स्कूटी लेकर दोनों फरार हो गए। बदमाशों ने महज बीस मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे दिया।

डीसीपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि, पुलिस की आठ टीमें वारदात के खुलासे के लिए लगाई गई हैं। पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। जल्द वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। बैंक के बाहर एक सीसीटीवी में बदमाशों के फरार होने के फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं। एक बदमाश पैदल दिख रहा है, जबकि दूसरा स्कूटी लेकर आता है। फिर दोनों स्कूटी पर बैठकर मौके से निकल जाते हैं।

डीसीपी ने बताया कि, पुलिस की तरफ से बार-बार समझाईश और पत्र लिखने के बाद भी वित्तीय संस्थान सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पूरी वारदात में बैंक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ताज्जुब की बात है 22 जनवरी से बैंक के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हुए थे। अलार्म सिस्टम तक ठप्प पड़ा हुआ था। बैंक परिसर में एटीएम बूथ के बावजूद वहां कोई गार्ड तैनात नहीं था।

संभावना जताई गई है कि बैंक की सुस्ती देख बदमाशों ने उसे लूटने का प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दे दिया। यदि बैंक मुस्तैद होती तो समय रहते बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होते।

भाजपा विधायक दल की बैठक, सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई

रीट की सी.बी.आई. जांच की मांग उठाई जाएगी। सतीश पूनिया पर हमले की घटना पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया

- भाजपा विधायक दल की बैठक में कटारिया, पूनिया और राठौड़ के समर्थन में 60 से अधिक विधायक, राजे के समर्थन में सिर्फ सिंघवी बोले।
- बारां मामले पर भी कटारिया, राठौड़ और पूनिया सहित 60 से अधिक विधायकों ने वसुंधरा की नहीं चलने दी, कहा प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा।
- रीट और सतीश पूनिया पर हमले के मामले मं वसुंधरा और सिंघवी को छोड़कर सभी विधायक एकजुट दिखे।

जयपुर, 8 फरवरी (का.सं.)। भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित पार्टी के 60 से अधिक विधायक मौजूद रहे।

वहीं, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहने के आसार हैं। भाजपा ने सत्तापक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले की निंदा की गई, साथ ही विधानसभा में रीट की सीबीआई जांच, प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला अपराध, किसानों की जमीन नीलामी, बेरोजगारी सहित संविदाकर्मियों के मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई गई है।

भाजपा विधायक दल की बैठक में रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया पर बूंदी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले, अलवर मूक बधिर नाबालिग पीड़िता मामला, किसान कर्ज़माफी, महिला सुरक्षा इत्यादि मुद्दों पर आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति पर चर्चा हुई और सतीश पूनिया पर हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया।

भाजपा विधायक दल की बैठक में गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड और सतीश पूनिया सहित 60 से अधिक विधायक जनहित के मुद्दों व सतीश पूनिया पर हमला मामले में एकजुट दिखे तो वसुंधरा राजे के समर्थन में सिर्फ प्रताप सिंह सिंघवी ही दिखे, जिन्हें भी अनुशासन में रहने की हिदायत दी गई।

विधायक दल की बैठक में गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और जोगेश्वर गर्ग ने संबोधित किया।

वहीं रीट पेपर लीक मामले की सी.बी.आई. जांच की मांग को लेकर महात्मा गांधी सर्किल पर भाजपा विधायकों के धरने में गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ वसुंधरा राजे सहित लगभग 67 विधायक मौजूद थे।

विधायकों के धरने में वसुंधरा राजे लगभग डेढ़ घंटे देरी से पहुंची और अपने साथ एकमात्र विधायक प्रतापसिंह सिंघवी को लेकर पहुंची। यह भी सियासी चर्चा का विषय बन चुका है कि भाजपा विधायकों के धरने में वसुंधरा राजे के बिना ही 65 विधायक पहुंच गये, और शायद वसुंधरा राजे को उम्मीद थी उनके बिना काफी विधायक धरने में नहीं आएंगे, लेकिन इसके उलट हुआ और नई सियासी चर्चा को जन्म दे दिया कि विधायक भी अब संगठन के नेतृत्व को मजबूती व अनुशासन को पूरी तरह अनुसरण करने लग गये हैं, जो भविष्य का बड़ा संकेत है।

चर्चा यह भी है कि, जब वसुंधरा राजे के बिना ही 65 विधायक भाजपा के धरने में पहुंचे तो डेढ घंटे बाद दिखावे के लिये ही सही राजे को मजबूरन धरने में आना पड़ा और वे बिना बोले ही चली गईं।

बैठक में सभी विधायकों को टास्क दिया गया है कि तीन साल में सरकार ने जो घोषणाएं की और पूरी नहीं हुई उनको भी सदन में उठाया जाए। हालांकी सदन में सत्ता पक्ष को घेरने से पहले ही विधायक दल की बैठक में एक बार फिर भाजपा में गुटबाजी भी सामने आयी।

प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर पत्थराव की घटना के विरोध में जब निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संगठन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा की सांसद दुष्यंत सिंह के बारां कार्यालय पर हमला हुआ तो पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं बोला।

ऐसे में सदन में सत्ता पक्ष को घेरने से पहले ही पार्टी अलग थलग नजर आ रही है। हालांकि उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा की हमले की हमने निंदा की थी और पुलिस के उच्च अधिकारी से भी बात की गई थी।

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया गुटबाजी की खबरों से पल्ला झाड़ते नजर आए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से जब गुटबाजी को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो पूनिया ने कहा कि, पार्टी के राजनीतिक मंच पर बैठते हैं तो चार चर्चाएं होती हैं। अपनी बात कहने का सबको हक है लेकिन सब पार्टी के निर्देशों को मानते हैं हम सब सदन में मजबूती से लड़ेंगे।

भाजपा विधायक दल की बैठक में बारां की घटना का जब राजे ने जिक्र किया तो कटारिया, राठौड़ और पूनिया ने कहा कि, हमने इसकी निंदा की और अनुशासहीनता करने वालों पर रिपोर्ट आने पर केन्द्रीय आलाकमान के निर्देशानुसार जल्द कार्यवाही होगी।

वहीं विधायक दल की बैठक में बोलने वाले सभी विधायकों ने रीट पेपर लीक सी.बी.आई. जांच की मांग और सतीश पूनिया पर हमला मामले को पुरजोर तरीके से उठाने की बात कही।

टेलीविजन पर मशहूर पौराणिक धारावाहिक ''महाभारत'' में ''भीम'' के किरदार को जीवंत करने वाले कलाकार प्रवीण कुमार का सोमवार देर रात निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार थे। प्रख्यात फिल्म निर्देशक बी आर चोपड़ा के निर्देशन में ''महाभारत'' में भीम के किरदार से प्रवीण को काफी लोकप्रियता मिली थी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। उनके परिवार में पत्नी, पुत्री, दो भाई और एक बहन हैं। उल्लेखनीय है कि, प्रवीण कुमार अभिनेता होने के साथ एक एथलीट भी थे। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एथलैटिक प्रतियोगिताओं में हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो स्पर्धा में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था और सन् 1966 के राष्ट्रमंडल खेलों में हैमर थ्रो में रजत पदक जीता था। इसके अलावा 1966 और 1970 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था।

आजम खान को जमानत नहीं मिली

नई दिल्ली, 8 फरवरी (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान की चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की गुहार वाली याचिका खारिज कर दी। पीठ ने याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वह (आजम खान) जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर शीघ्र सुनवाई की गुजारिश कर सकते हैं।

खान ने अपनी याचिका में राज्य की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया था कि वह उनसे संबंधित अदालती मामलों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में जानबूझकर देरी कर रही है। इसी वजह से उन्हे अंतरिम जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

कर्नाटक में हिजाब के संबंध में छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हुआ

स्थिति बिगड़ती देख मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने स्कूल-कॉलेजों में तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की

- कर्नाटक के कई कॉलेज परिसरों में हिजाब और भगवा स्कार्फ पर प्रतिबंध के विरोध में मंगलवार को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां एक कॉलेज में हुई हिंसक झड़प में तीन छात्र घायल हो गये।

बेंगलुरु, 8 फरवरी (वार्ता)। कर्नाटक के कॉलेज परिसरों में हिजाब और भगवा स्कार्फ पर प्रतिबंध के विरोध में मंगलवार को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बागलकोट में पथराव की सूचना मिली है।

पुलिस ने कहा, यह झड़प हिजाब पहने छात्रों और भगवा स्कार्फ में आए एक अन्य छात्रों के समूह के बीच हुई बहस के बाद हुई। पुलिस ने कहा कि इस विवाद को लेकर हुए झड़प में तीन छात्र घायल हो गए हैं। तनाव बढ़ने पर रबाकविबनहट्टी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रबंधन ने छुट्टी की घोषणा कर दी। घटना की सूचने मिलते ही पुलिस अधीक्षक लक्ष्मीप्रसाद और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं विजयपुरा जिला स्थित शांतेश्वर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रवेश द्वार पर हिजाब और भगवा स्कार्फ पहने छात्रों को रोक दिया, जिसके बाद छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने का समर्थन करने वाला एक अन्य समूह नीले रंग का स्कार्फ पहन कर आया, जिससे वहां अराजकता फैल गई। पुलिस ने हालांकि स्थिति को नियंत्रित कर लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब और भगवा स्कार्फ पहनने को लेकर बढ़ते विवाद को देखते हुए हाई स्कूल और कॉलेजों में अगले तीन दिनों तक छुट्टी की घोषणा कर दी है। बोम्मई ने मंगलवार को दिल्ली में यह आदेश जारी किया। उन्होंने राज्य के विद्यार्थियों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों तथा राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने और सभी संबंधितों से सहयोग की अपील भी की है।

जयपुर जिले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी पर्याप्त जमीन और संबंधित एजेंसियों से आवश्यक मंजूरी के बिना भूखंडों की बुकिंग कर रही है। पुलिस ने कहा कि राणा के सामने आने के बाद से इस मामले में करीब तीन करोड़ रुपये की कुल 51 शिकायतें मिली हैं। निवेशकों से जुटाए गए पैसे को कंपनी के निदेशकों ने कथित तौर पर हड़प लिया। कंपनियों के रजिस्ट्रार से एकत्र किए गए रिकॉर्ड ने स्थापित किया कि आरोपी और एक अन्य फरार आरोपी कमल सिंह निदेशक हैं और कंपनी में प्रत्येक की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने निवेशकों को प्रस्तावित भूखंडों और सुविधाओं के भविष्य के मूल्य के बारे में झूठे सपने दिखाकर अपनी ओर आकर्षित किया।

'राहुल गांधी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अहमदाबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुये, श्रीमती सिद्धू ने कहा कि, सर्वोच्च पद के लिए किसी व्यक्ति का चयन करते समय उसकी शिक्षा पर विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी को गुमराह किया गया जिसके कारण उन्होंने चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया।

उन्होंने कहा, उनके पति सिद्धू मुख्यमंत्री प्रत्याशी होने के लिये सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं।

ज्ञातव्य है कि राहुल ने शनिवार को लुधियाना की एक सभा में मुख्यमंत्री के चेहरे के रुप में चन्नी के नाम की घोषणा की थी।

राहुल द्वारा मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी न बनाये जाने से नवजोत सिंह सिद्धू आहत हुये, लेकिन अब तक वे खामोश हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि, वे एक-दो दिन में विरोध की अपनी रणनीति उजागर कर सकते हैं। इन लोगों का कहना है कि पत्नी की टिप्पणी से उनका (सिद्धू का) कोई लेना-देना नहीं है।

पैगसस द्वारा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिबद्ध लोगों ने इस बात का पूरा खुलासा कर दिया है कि, इज़रायल की सर्वेलैंस फर्म एन.एस.ओ. ग्रुप ने पैगसस जासूसी सॉफ्टवेयर आधिकारिक एवं प्रामाणिक सरकारों को बेचा था, जिन्होंने इसे फोन हैक करने के काम में लिया। अब इज़रायल सरकार ने कहा है कि, वह इन दावों की छानबीन करेगी कि, इज़रायली पुलिस ने अदालती आदेश के बिना इस स्पायवेयर का उपयोग यहाँ के नागरिकों के खिलाफ किया था।

न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि, इन आरोपों के कारण इज़रायल के पूर्व प्रधानमंत्री बैंजामिन नेतान्याहू के भ्रष्टाचार संबंधी मुकदमे में भी थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, क्योंकि ये दावे किये गये हैं कि, पुलिस ने मुकदमे के एक मुख्य गवाह का फोन गैर कानूनी तौर पर हैक कर लिया था।

इज़रायली मीडिया ने पिछले माह ऐसे दावों की जानकारी देना शुरु कर दिया था कि, इज़रायली पुलिस ने एन.एस.ओ. के प्रमुख उत्पाद, पैगसस का उपयोग, स्थानीय ऐक्टिविस्टों, राजनेताओं, व्यावसायियों, अफसरशाहों तथा नेतान्याहू के आलोचकों तथा उनसे जुड़े लोगों के फोनों से जानकारी हासिल करने के लिये किया था। इज़रायल के एक बिज़नैस दैनिक ने ऐसे दर्जनों नागरिकों की सूची जारी की थी, जिनके फोन हैक किये गये थे।

75,000 करोड़...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होने वाले मराठी दैनिक ''देशोन्नति'' के संपादक प्रकाश पोहारे कहते हैं कि, एडवोकेट तिवारी द्वारा उठाया गया मुद्दा काफी गंभीर है क्योंकि लाखों लोगों को कोविड पॉज़िटिव के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अस्पतालों में भर्ती कराया गया और वहां पर कथित उपचार के नाम पर लाखों रूपए वसूले गए। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने धन की रिकवरी के लिए इन अस्पतालों और अनधिकृत लैब्स के विरूद्ध मुकदमे दायर करने चाहिए।

मेघालय में वह कर दिखाया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वामपंथी विचारधारा कम से कम अपनी पकड़ तो बना ही रही है।

वास्तव में, पूरे देश के ये राजनीतिक घटनाक्रम भारतीय राजनीति में कुछ मूलभूत बदलावों का संकेत हैं।

भारत की पुरानी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस एक के बाद एक राज्य में अपना जनाधार खो रही है। ऐसे लोग भी हैं, जो कांग्रेस के लिए यह भी कहते हैं कि इसमें नए प्रासंगिक विचारों की कमी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक गुट पार्टी संचालन के तरीकों में बदलाव के सुझाव देने और अपने खुले विद्रोह के लिए जाना जाता है। एक ही पार्टी का बोलबाला पार्टी की प्रतिस्पर्धात्मक स्पर्धा का निश्चित रुप से गला घोंट रहा था। पार्टी के एक परिवार के प्रति निर्विवाद निष्ठा रखने के कारण ही अक्षम लोगों को महत्व दिया जा रहा है।

कांग्रेस के जिन विधायकों ने कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली एम.डी.ए. गठबंधन सरकार को अपना समर्थन दिया, उन्होंने कांग्रेस भी नहीं छोड़ी है। उन्होंने स्वयमेव अपने स्तर पर ही यह निर्णय लिया है। पांचों विधायकों ने एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनकी कार्यवाही राज्य के वृहद् हित और उसके विकास के अनुरुप है। उनमें से किसी ने भी किसी तरह से यह संकेत नहीं दिया है कि वे अपनी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए हैं।

उन्होंने सिर्फ अपनी समझ से कॉनराड संगमा सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में इन पांचों ने उम्मीद जतायी है कि, पार्टी आलाकमान उनकी इस कार्यवाही का समर्थन करेगा।

यह स्थिति गत वर्ष के अंतिम दिनों में पैदा हुई, जब तृणमूल कांग्रेस ने नेताओं को कांग्रेस से टी.एम.सी. में लाने की व्यवस्था की थी। उस समय, राज्य विधानसभा के 17 सदस्यों में से 12 सदस्य कांग्रेस छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गये थे।

तथापि, शेष कांग्रेस विधायक अब एम.डी.ए. गठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे हैं तथा तृणमूल एकमात्र विपक्षी दल के रूप में पीछे छूट गई है। सामान्य तौर पर वैसे तो, इससे तृणमूल खुश होती तथा उसका उत्साह बढ़ गया होता।

लेकिन पार्टी ने नाराजगी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा है कि, ''सत्ता के भूखे'' लोगों ने मौजूदा सरकार को समर्थन दे दिया है। नाराजगी का कारण यह है कि, अब कांग्रेस के पाँच विधायकों द्वारा सरकार का समर्थन कर देने के बाद, तृणमूल के राजनैतिक भविष्य की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

राज्य के मौजूदा तृणमूल सदस्य, जो कांग्रेस छोड़कर आये हैं, नई बदली हुई स्थिति में अपनी स्थिति में यथावत् नहीं रह पायेंगे। आशंका यह है कि, टी.एम.सी. में शामिल हुये कई विधायक टी.एम.सी. की नाव को उलटकर, उसे छोड़ जायेंगे।

यह तो मामूली सा परिणाम है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य मेघालय ने पूरी तरह अप्रत्याशित एवं सोच से परे की स्थिति संभव बना दी है। हो सकता है कि यह स्थिति शेष भारत तक भी पहुँच जाये।

अडानी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वी.एन.एल.) की ओर से प्रस्तुत हुये अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली बैंच को अडानी पावर (मुन्द्रा) लिमिटेड के साथ हो चुके समझौते के बारे में बताया, इसलिये बैंच को अदालत के 2019 के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका की सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी, जिस फैसले में इस प्राइवेट फर्म के पावर परचेज एग्रीमेंट (पी.पी.ए.) को समाप्त करने के फैसले को बहाल रखा गया था। बैंच, जिसमें न्यायमूर्ति यू.य. ललित, डी.वाई. चन्द्रचूड़, भूषण आर. गवई तथा सूर्य कान्त शामिल थे, ने कहा कि, बैंच इस बात को रिकॉर्ड पर लेते हुये इस केस को बंद कर देगी कि, दोनों पक्ष सैटलमेंट एग्रीमेंट द्वारा नियंत्रित रहेंगे।

अडानी परिवार ने पी.पी.ए. को रद्द कर दिया था, क्योंकि गुजरात मिनरल डवलपमैंट कॉर्पोरेशन कोयला-आपूर्ति नहीं कर रहा था तथा सर्वविदित है कि, बिजली की आपूर्ति कोयले की सप्लाई पर निर्भर होती है। गुजरात इलैक्ट्रिसिटी रेग्यूलेटरी कमीशन ने इसे गैर कानूनी माना, लेकिन जुलाई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बैंच ने अडानी के कार्य को कानून सम्मत तथा वैध माना तथा सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी रेग्यूलेट्री कमीशन से कहा कि, वह अडानी पावर द्वारा स्टेट पी.एस.यू. को दी गई बिजली के लिये क्षतिपूरक शुल्क तय करे। कमीशन ने अडानी पावर को 1100 करोड़ रू. का मुआवज़ा दिया जाना तय किया था।

मोदी सरकार ने पत्रकारों के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वह हिस्सा रहा हो, या फिर उस पत्रकार ने उस प्रतिष्ठान को छोड़ दिया हो।

नई नीति में यह निषिद्ध है कि, कोई पत्रकार सोशल मीडिया, विज़िटिंग कार्ड या अपने लैटरहैड आदि पर ''भारत सरकार से मान्यता प्राप्त'' होने का उल्लेख करे।

केवल मान्यता प्राप्त पत्रकार ही दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में प्रवेश पा सकते हैं, तथा ऐसे समारोहों एवं कार्यक्रमों, जिनमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मौजूद हैं, में प्रवेश के लिये भी पत्रकार का मान्यता प्राप्त होना जरूरी है।

नई नीति में, ऑनलाइन समाचार प्लेटफॉर्मों के लिये काम करने वाले पत्रकारों की मान्यता के लिये भी गाइडलाइन तैयार की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है।

किन्तु समाचारों का एकत्रीकरण या संकलन करने वाले लोगों के लिए यह लागू नहीं होगा।

नीति कहती है कि, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अस्तित्व में आये एक वर्ष के अधिक समय हो चुका हो तथा वैबसाइट की ''पिछले छः माह की औसत मासिक यूनिक विज़िटर संख्या, जो वैबसाइट के सी.ए.जी. अनुमोदित/पैनल में शामिल ऑडिटरों द्वारा समुचित रूप से प्रमाणित हो'' की रिपोर्ट देना जरूरी है।

ऐसी वैबसाइट के एक पत्रकार को मान्यता प्रदान की जा सकेगी, जिसके पास 10 से 50 लाख तक यूनिक विज़िटर प्रति माह हों, जबकि 1 करोड़ से अधिक यूनिक विज़िटर प्रति माह वाली वैबसाइट के चार पत्रकारों को मान्यता दी जा सकती है।

अखबारों, साप्ताहिक या पाक्षिक पत्रिकाओं, समाचार एजेंसियों, विदेशी प्रकाशनों, टी.वी. चैनलों या एजेंसियों तथा भारतीय टी.वी. समचार चैनलों में काम कर रहे पत्रकार भी मान्यता के पात्र हैं, किन्तु इसके लिये प्रत्येक प्लेटफॉर्म के आकार को आधार माना जायेगा।

इस समय 2457 पी.आई.बी. मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। ऊपर बताये गये प्रतिष्ठानों में काम करने वाले पत्रकारों के अलावा, 15 साल से अधिक अनुभव रखने वाले फ्रीलान्सर तथा 30 वर्ष से ज्यादा अनुभव वाले पुराने पत्रकार, 65 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वाले लोग, जिनका सार्वजनिक रूप से अभिनन्दनीय कैरियर रहा हो, भी मान्यता प्रदान किये जाने के पात्र होंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, मोदी सरकार अपने विरोधियों पर दबाव डालती आ रही है तथा अब इसने जानकारी के स्रोत को भी काबू में लेने का निश्चय कर लिया है।

इन नये नियमों के फलस्वरूप, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया वाले देश की छवि वाले भारत की छवि का और ज्यादा खराब होना तय है। ज्ञातव्य है कि, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया का होना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त एवं मानक है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908